

प्रेषक,

आर0के0तोमर,  
संयुक्त सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक,  
उत्तराखण्ड, देहरादून।

वन एवं पर्यावरण अनुभाग-2

देहरादून दिनांक ७ सितम्बर 2017

विषय: वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-27 के अंतर्गत राज्य सैक्टर योजना "वन पंचायतों की सुदृढ़ीकरण योजना" हेतु स्वीकृत आय-व्ययक के सापेक्ष अवशेष धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन उत्तराखण्ड के पत्र संख्या नि0-183/3-5(व0प0सु0) दिनांक 18.07.2017 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान सं0-27 के अंतर्गत राज्य सैक्टर योजना "वन पंचायतों की सुदृढ़ीकरण योजना" हेतु आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि ₹136.70 लाख के सापेक्ष शासनादेश सं0-1087/X-2-2017-12(39)2012 दि0 12.6.2017 द्वारा स्वीकृत लेखानुदान की अवमुक्त धनराशि ₹45.56 लाख को समायोजित करते हुए वर्तमान में ₹57.81 लाख (रस्त्तावन लाख इक्यासी हजार मात्र) की धनराशि निम्न तालिका में अंकित विवरणानुसार अवमुक्त कर व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्न शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :—

अनुदान संख्या-27

(धनराशि हजार ₹ में)

लेखाशीर्षक	आवंटित धनराशि
2406—वानिकी तथा वन्य जीवन	
01—वानिकी	
101—वन संरक्षण विकास तथा सम्पोषण	
09—वन पंचायतों की सुदृढ़ीकरण योजना	
04—यात्रा व्यय	567
08—कार्यालय व्यय	333
11—लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	147
15—गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	200
18—प्रकाशन	67
25—लघु निर्माण कार्य	2000
29—अनुरक्षण	467
42—अन्य व्यय	1000
44—प्रशिक्षण व्यय	1000
योग	5781

(रस्त्तावन लाख इक्यासी हजार मात्र)

1. धनराशि का व्यय वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-610/3(150)XXVII(1)/2017 दिनांक 30.6.17 में दिये गये दिशा—निर्देशों एवं प्रतिबन्धों अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाये।
2. अवमुक्त की जा रही धनराशि से मात्र योजना से सम्बन्धित कार्य ही कराया जाना सुनिश्चित करें एवं ऐसे कार्य न कराए जिन हेतु राज्य सैक्टर में अलग से योजना उपलब्ध हैं, यदि योजना से इतर कार्यों को कराना पाया गया तो इस हेतु सम्बन्धित अधिकारी उत्तरदायी होगा।
3. कार्यों को कराये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि सम्बन्धित कार्य अन्य विभागीय योजनाओं में पूर्व से स्वीकृत/कराया न हो।

.....2

4. बजट प्राविधान किसी भी लेखा शीर्षक/मद के अन्तर्गत व्यय की अधिकतम सीमा को ही प्राधिकृत करता है। अतः बजट प्राविधान से अधिक किसी भी दशा में न तो व्यय किया जाय और न ही पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में कोई व्यय भार/दायित्व सृजित किया जाय।
5. योजनाओं की विभिन्न मदों पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों एवं आदेशों के अनुसार ही किया जाये तथा जहां आवश्यकता हो सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त करने उपरान्त ही कार्य किये जाय।
6. मानक मद 25—लघु निर्माण कार्य में आवंटित धनराशि से प्रस्तावित निर्माण कार्यों में से किसी भी कार्य की लागत ₹5.00 लाख से अधिक न हो तथा वृहद् निर्माण कार्य की लागत ₹5.00 लाख से कम करने के लिए उसके टुकड़े न किये जाए। सर्वप्रथम गत वर्षों के अवशेष कार्य पूर्ण किये जाय तदोपरांत ही नए कार्यों हेतु धनराशि अवमुक्त की जाय।
7. किसी भी शासकीय व्यय हेतु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 (लेखा नियम) भाग-1 एवं खण्ड-7 (वन लेखा नियम), आय-व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल), उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रैक्योरमेंट) नियमावली, 2017, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के शासनादेश तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2— उक्त सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में स्वीकृत आय-व्ययक के सापेक्ष अनुदान संख्या-27 के अन्तर्गत उपरोक्त तालिका में वर्णित लेखाशीर्षक की सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जायेगा। कम्प्युटरीकृत अलोटमैन्ट आई0डी0— S1709270162 दिनांक 25.09.2017 संलग्न है।

3— यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-610 / 3(150)XXVII(1)/2017 दिनांक 30.6.17 के अनुपालन में जारी किये जा रहे हैं।

संलग्न : यथोक्त।

भवद्वीय,  
(आर0के0तोमर)  
संयुक्त सचिव

संख्या—1650 / X—2—2017—12(39)2012 तदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार(ए एण्ड ई), उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. महालेखाकार (आडिट), उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. वित्त अनुभाग-4 / नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
6. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, देहरादून।
7. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन, सचिवालय, देहरादून।
8. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. एन.आई.सी., उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. गार्ड फाईल।

Me  
(आर0के0तोमर)  
संयुक्त सचिव

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20172018

Secretary, Forest (S016)

आवंटन पत्र संख्या - 1650/X-2-2017-12(39)2012

अनुदान संख्या - 027

अलोटमेंट आई डी - S1709270162

आवंटन पत्र दिनांक - 25-Sep-2017

HOD Name - Principal Chief Conservator of Forest (4260)

1: लेखा शीर्षक 2406 - वानिकी तथा वन्य जीवन 01 - वानिकी  
 101 - वन संरक्षण विकास तथा सम्पोषण  
 09 - वन पंचायतों की सुदृढीकरण योजना (2406 01 800 34 से स्थानान्तरित)  
 00 - 0

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	Voted
04 - यात्रा व्यय	283000	567000	850000
08 - कार्यालय व्यय	167000	333000	500000
11 - लेखन सामग्री और फार्मों की छ	73000	147000	220000
15 - भाड़ियों का अनुरक्षण और बेट्टे	100000	200000	300000
18 - प्रकाशन	33000	67000	100000
24 - बहत निर्माण कार्य	1667000	0	1667000
25 - लक्ष्य निर्माण कार्य	1000000	2000000	3000000
29 - अनुरक्षण	233000	467000	700000
42 - अन्य व्यय	500000	1000000	1500000
44 - प्रशिक्षण व्यय	500000	1000000	1500000
	<b>4556000</b>	<b>5781000</b>	<b>10337000</b>

Total Current Allotment To Head Of The Department In Above Schemes - **5781000**

*M.S*

